■ संपादकीय

अलग-थलग पड़ता पाक

विभिन्न मंचों से कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की पाक की कोशिश को विफल करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के मंच का भारत ने भरपूर उपयोग किया है। आतंकवाद के मुद्दे पर अलग–थलग पड़े पाक ने भारत को निशाने पर लेने के लिये कभी संयुक्त राष्ट्र में गत सप्ताह हुए इस्लामिक देशों के संगठन का सहारा लिया तो कभी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सम्मेलन को भारत के विरुद्ध हथियार बनाया। जिसका भारत ने पाक को आतंक की पाठशाला बताकर माकूल जवाब भी दिया। न्यूयार्क दौरे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के साथ मिलकर पाक की छद्म नीतियों से अवगत कराया। वहीं जापानी विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद अपरोक्ष रूप से पाक–चीन को घेरा कि उत्तर कोरिया यदि आज परमाणु हथियारों के जरिये दुनिया को डरा रहा है तो वे देश भी कटघरे में आने चाहिए ,जिन्होंने उत्तर कोरिया को विनाश के हथियार उपलब्ध कराने में सहयोग किया। सही मायनों में वह उत्तर कोरिया में परमाणु प्रसार गतिविधियों में शामिल देशों को जांच के दायरे में लाने की बात कर रही थीं। निश्चित तौर पर इससे पाकिस्तान की कारगुजारियां दुनिया के सामने बेनकाब होती हैं।

फिर ब्रिक्स सम्मेलन में चीन की मौजूदगी में पाकिस्तान का आतंकवाद को समर्थन का एजेंडा निशाने पर आ गया था। जिससे तिलमिलाकर पाक भारत पर अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश में है। मगर अमेरिका, जापान समेत पश्चिमी देशों का भारत को मिलने वाला समर्थन पाक की बेचैनी बढ़ाने वाला है। अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जगत की चिंताओं को समझते हुए अपने यहां लश्कर-ए-तय्यबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों पर रोक लगानी ही होगी। यह भी एक हकीकत है कि पाक में जारी राजनीतिक अस्थिरता और पर्दे के पीछे से सेना व आईएसआई की भूमिका के चलते इसकी संभावना कम ही नजर आती हैं।

निःसंदेह, आने वाले दिनों में जब 72वीं संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में भारत का आधिकारिक वक्तव्य आयेगा तो निशाने पर पाक पोषित आतंकवाद ही होगा। दरअसल, हाल के दिनों में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों के संरक्षण के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति की बेबाक टिप्पणी आई थी। फिर ब्रिक्स सम्मेलन में चीन की मौजूदगी में पाकिस्तान का आतंकवाद को समर्थन का एजेंडा निशाने पर आ गया था। जिससे तिलमिलाकर पाक भारत पर अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश में है। मगर अमेरिका, जापान समेत पश्चिमी देशों का भारत को मिलने वाला समर्थन पाक की बेचैनी बढ़ाने वाला है। अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जगत की चिंताओं को समझते हुए अपने यहां लश्कर–ए–तय्यबा और जैश–ए–मोहम्मद जैसे संगठनों पर रोक लगानी ही होगी। यह भी एक हकीकत है कि पाक में जारी राजनीतिक अस्थिरता और पर्दे के पीछे से सेना व आईएसआई की भूमिका के चलते इसकी संभावना कम ही नजर आती हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला संबोधन निराश करने वाला ही था।

■ जीने का सलीका

एक राजा था। उसने आज्ञा दी कि संसार में इस बात की खोज की जाय कि कौन से जीव-जंतु निरुपयोगी हैं। बहुत दिनों तक खोज बीन करने के बाद उसे जानकारी मिली कि संसार में दो जीव जंगली मक्खी और मकड़ी बिल्कुल बेकार हैं। राजा ने सोचा, क्यों न जंगली मक्खियों और मकड़ियों को ख़त्म कर दिया जाए।

इसी बीच उस राजा पर एक अन्य शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया, जिसमें राजा हार गया और जान बचाने के लिए राजपाट छोड़ कर जंगल में चला गया। शत्रु के सैनिक उसका पीछा करने लगे। काफ़ी दौड़-भाग के बाद राजा ने अपनी जान बचाई और थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी एक जंगली मक्खी ने उसकी नाक पर डंक मारा जिससे राजा की नींद खुल गई। उसे ख़याल आया कि खुले में ऐसे सोना सुरक्षित नहीं और वह एक गुफ़ा में जा छिपा। राजा के गुफ़ा में जाने के बाद मकड़ियों ने गुफ़ा के द्वार पर जाला बुन दिया।

शत्रु के सैनिक उसे ढूँढ ही रहे थे। जब वे गुफ़ा के पास पहुँचे तो द्वार पर घना जाला देख कर आपस में कहने लगे, अरे! चलो आगे। इस गुफ़ा में वह आया होता तो द्वार पर बना यह जाला क्या नष्ट न हो जाता। गुफ़ा में छिपा बैठा राजा ये बातें सुन रहा था। शत्रु के सैनिक आगे निकल गए। उस समय राजा की समझ में यह बात आई कि संसार में कोई भी प्राणी या चीज़ बेकार नहीं। अगर जंगली मक्खी और मकड़ी न होतीं तो उसकी जान न बच पाती। इस संसार में कोई भी चीज़ या प्राणी बेकार नहीं। हर एक की कहीं न कहीं उपयोगिता है।

■ ज्ञान की परख

1. प्रधानमंत्री ने डोंगरगढ़ में किस योजना की घोषणा की?
2. टेस्ट मैच में सबसे तेज शतक किसने बनाया है?
3. रिंगिंग बेल्स के सीईओ कौन हैं?
4. पश्चिम बंगाल में कौन मुख्यमंत्री बनी हैं?
5. छत्तीसगढ़ की किस महिला लोक कलाकार को पद्मश्री? सम्मान दिया गया?

1. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 2. ब्रैंडन मैकुलम 3. मोहित गोयल 4. ममता बैनर्जी 5. ममता चंद्राकर

ब्रिक्स में मोदी की कूटनीतिक जीत

हमारे पड़ोसी देश चीन के साथ हमने जब भी सदाशयता दिखाई चीन ने उसे हमारी कमजोरी समझा है। केन्द्र में प्रधानमंत्री पद की बागडोर नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ हाथों में आने के बाद भी चीन से दोस्ताना संबंध कायम करने की पुरजोर कोशिश की गई परंतु चीन ने कभी भी सदाशयता दिखाने की जरूरत महसूस नहीं की। हमारे दूसरे पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने में उसे कुछ खोट नहीं आई उल्टे वह पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जताता रहा जिसका एकमात्र उद्देश्य पाकिस्तान से अधिकतम आर्थिक हित साधना ही रहा है परंतु पाकिस्तान ने चीन की इस चाल को कभी गंभीरता से नहीं लिया।

कृष्णमोहन झा

उसे तो चीन से दोस्ती में ही अपनी भलाई दिखीं है, लेकिन पाकिस्तान को कभी यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि कभी ऐसा दिन भी आ सकता है जब चीन को पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ बोलने की मजबूरी का सामना करना पड़ेगा। इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कूटनीतिक विजय ही माना जाना चाहिए कि चीन के अंदर ही आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के घोषणापत्र में चीन की अनिच्छा के बावजूद पाकिस्तान में फलफूल रहे चार आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर चिंता जताई है। इसके पूर्व चीन ने भारत से कहा था कि वह ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा न उठाए परंतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन को कूटनीतिक सबक सिखाने की पहले ही ठान ली थी इसलिए चीन की आपत्ति के बावजूद उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और उसे ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में शामिल करवाने में सफल रहे। चीन के शियामेन शहर में आयोजित ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेन के 43 पृष्ठीय घोषणा पत्र में जिन 10 आतंकवादी संगठनों का उल्लेख किया गया है उनमें पाकिस्तान में फलफूल रहे चार आतंकी संगठनों के नामों का भी जिक्र है। ये संगठन हैं- अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और तहरीफ ए तालिबान पाकिस्तान। इस घोषणा पत्र में 17 जगह आतंकवाद का जिक्र किया गया है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में पाक पोषित आतंकी संगठनों के नाम शामिल किए गए जाने के लिए भारत ने सर्वाधिक जोर दिया था। चीन ने पाकिस्तान के अपनी दोस्ती को देखते हुए भारत से पहले ही यह अनुरोध किया था कि वह ब्रिक्स के मंच पर आतंकवाद का मुद्दा न उठाए क्योंकि भारत की अपनी कुछ चिंताओं के बावजूद यह ब्रिक्स के मंच पर उठाने का विषय नहीं है। परंतु प्रधानमंत्री मोदी के सख्त रूख का दूसरे सदस्य देशों ने भी समर्थन किया तो चीन को आखिरकार झुझना पड़ा और पाकिस्तान पोषित 4 आतंकी संगठनों के नाम ब्रिक्स के घोषणा पत्र में शामिल कर लिए गए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जोर देने पर ही घोषणा पत्र में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा करते हैं चाहे (आतंकी हमले) किसी के द्वारा और कही भी हुए हों। दरअसल चीन के लिए अब असमंजस की स्थिति बनना तय है क्योंकि उसने संयुक्त राष्ट में मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। अब देखना यह है कि भविष्य में चीन इस तरह का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट में आने पर क्या रूख अपनाता है। यहां यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि गत वर्ष कश्मीर के उड़ी स्थित सेना मुख्यालय पर आतंकी हमले के बाद जब गोवा में ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई थी तब चीन ने उस बैठक के प्रस्ताव के मसौदे में पाक पोषित आतंकी संगठनों के नाम नहीं जुड़ने दिए थे जबकि भारत ने इसके लिए विशेष आग्रह किया था। चीन को पूरी उम्मदी थी कि इस बार ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन उसी की धरती पर आयोजित किया जा रहा है इसलिए उसकी सहमति के बिना आतंकवाद का मुद्दा उठाने में भारत को इस बार भी सफलता नहीं मिलेगी परंतु इस बार प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति के आगे उसे परास्त होना पड़ा। शियामेन घोषणा पत्र की जो भाषा है उसे भी चीन को मन मसोसकर स्वीकार करना पड़ा होगा। यद्यपि घोषणा पत्र में पाकिस्तान का सीधे सीधे नाम नहीं लिया गया है परंतु ब्रिक्स देश इस हकीकत से भली भांति वाकिफ है कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन फलफूल रहे है उन्हें खाद पानी उपलब्ध कराने में पाकिस्तानी सरकार की हमेशा से ही दिलचस्पी रही है। घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि आतंकवाद करने वाले और उसे सहयोग देने वाले देशों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

अब जबकि ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में चीन को आतंकवाद के मुद्दे पर दूसरे सदस्य देशों के दृष्टिकोण से सहमत होना पड़ा है तब उसे पाकिस्तान सरकार को सफाई भी देना पड़ेगी कि ऐसा करना उसकी मजबूरी थी क्योंकि ऐसा न करने पर ब्रिक्स में उसे अलग थलग होना पड़ता। अब देखना यह है कि चीन क्या पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव बनाने की आवश्यकता महसूस करेगा कि वह अपने देश की सीमा के अंदर किसी भी आतंकी संगठन को अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति न दे। इसकी संभावना अभी तो नगण्य ही नजर आती है। फिर भी चीन को अब यह बात समझ में आ जाना चाहिए कि वह अकेला पाकिस्तान की पीठ थपथपाकर आतंकवाद के मुद्दे पर अलग राग नहीं अलाप सकता।

गौरतलब है ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के उदघाटन में ही शी जिनपिंग ने अपने भाषण में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आव्हान किया था। उन्होंने इसके मूल कारणों और लक्षण से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया था। चीन के राष्ट्पति का आशय साफ था कि आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा के समय उसके मित्र पाकिस्तान पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी निशाना न साधा जाए परंतु चीन की मंशा पूरी नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री मोदी के चीन रवाना होने के पूर्व ही भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दो टूक शब्दों में चीन को आगाह कर दिया था कि दूसरा देश यह तय नहीं कर सकता कि सम्मेलन में भारत की ओर से क्या कहा जाए। ऐसा करके चीन दूसरे देश के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत के साथ जब प्रभावशाली तरीके से आतंकवाद के मुद्दे पर अपने विचार रखे तो ब्राजील, रूस व दक्षिण अफ्रीका ने भारत के पक्ष में अपनी राय जाहिर की और अंततः चीन को सबकी हां में हां मिलानी पड़ी।

परिवारशाही की गिरफ्त में लोकतंत्र

लगता है अब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन ही जाएंगे, और भले ही वे कोई भी तरीका अपना लें यह पद संभालने का, उनके सीने पर परिवारवाद का तमगा तो चमकता ही रहेगा। अपना अध्यक्ष चुनना कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वे जिसे योग्य समझें, अपना अध्यक्ष बना सकते हैं। योग्यता के उनके मानदंड भी कांग्रेस वाले स्वयं निर्धारित करने के अधिकारी हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि भारत की राजनीति में राजनीतिक परिवार से जुड़ा होना भी योग्यता का एक बड़ा मानदंड है। हाल ही में जब कांग्रेस के उपाध्यक्ष अमेरिका की यात्रा पर गये थे तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर एक सभा रखी थी वहां।

विश्वनाथ सचदेव

पहले भी हमारे राजनेता विदेशों में छोटे-मोटे आयोजन करते रहे हैं, पर विदेश-यात्राओं में शानदार आयोजनों की परंपरा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने ही शुरू की है। पर वे सिर्फ भाषण देते हैं। एकतरफा संवाद होता है उनका। राहुल गांधी ने प्रश्नोत्तर का रास्ता चुना। वहां उनसे एक सवाल पूछा गया था भारतीय राजनीति में परिवारवाद के संदर्भ में। उत्तर उन्हें देना ही था। उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि 'हिन्दुस्तान में तो परिवारवाद ही चलता है।' हालांकि, उन्होंने यह बात हल्के-फुल्के अंदाज में ही कही थी, और फिर राजनीति में 'योग्यता' की आवश्यकता रेखांकित करने की कोशिश भी उन्होंने की। पर 'ऐसा ही चलता है' वाली बात चिपक गयी।

कांग्रेस के विरोधियों ने इसे जहां एक ओर परिवारवाद की वकालत के तर्क के रूप में देखा, वहीं यह भी कहा कि 'कांग्रेस के युवराज' ने विदेश की भूमि पर जाकर देश का अपमान किया है। अब जहां तक अपमान का सवाल है, तो देश का अपमान तो इस तथ्य से हो रहा है कि भले ही हमने राजशाही को समाप्त कर दिया हो, पर देश के सभी दलों में परिवारशाही के रंग दिखाई दे रहे हैं। कहीं रंग गहरा है, कहीं कम गहरा। पर हकीकत यह है कि जनतांत्रिक भारत की राजनीति परिवारवाद के ग्रहण से लगातार ग्रस्त होती जा रही है। कांग्रेस पचास-साठ साल तक देश पर शासन करती रही है, इसलिए उसका परिवारवाद ज़्यादा गहरा और फैला हुआ दिखता है, लेकिन हकीकत यह है कि उसके बाद भी जो दल सत्ता में आये, इनमें भाजपा शामिल है, वे भी इस बीमारी से मुक्त नहीं रह पाये। आज देश में स्थिति यह है कि लगभग सभी राज्यों में, और सभी दलों में, बहुत से चुनाव-क्षेत्रों पर परिवारों का कब्जा है। उन्हें अपनी मलकियत लगने लगे हैं चुनाव-क्षेत्र। पिता के बाद बेटा-बेटी, पत्नी या बहन के नाम कर दी जाती है चुनाव-क्षेत्र की जागीर।

यह परिवारवाद कितनी गहराई से हमारी राजनीति में जड़ें जमा चुका है, इसका एक उदाहरण ये आंकड़े हैं – आज यानी हमारी वर्तमान संसद में तीस वर्ष से कम उम्र के सारे सांसद वंशगत राजनीति का लाभ उठाकर चुनाव जीते हैं। यदि उम्र का पैमाना थोड़ा बढ़ाया जाये तो चालीस से कम उम्र वाले दो-तिहाई सांसद ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक परिवारों का होने का लाभ मिला है। लोकसभा में हमारे सत्ताइस सांसद तो ऐसे हैं जो नाते-रिश्तेदारों के संदर्भ में 'बहुवंशवादी' कहे जा सकते हैं। जहां तक क्षेत्रीय दलों का सवाल है, शायद ही कोई ऐसा दल होगा जो इस वंशवाद का शिकार न हो। उत्तर प्रदेश में मुलायमसिंह के कुनबे ने समाजवाद की राजनीति पर कब्ज़ा कर रखा है, बिहार में लालू अपने बेटे-बेटियों को राजनीति में 'जमाने' में लगे हैं। उत्तर में जम्मू-कश्मीर में जहां एक ओर शेख अब्दुल्ला के वारिस राजनीति पर अपना हक जताये हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ पीडीपी की नेता को भी पार्टी विरासत में मिली है। धुर दक्षिण में द्रमुक और अन्नामुद्रक में परिवारों का बोलबाला है। पंजाब में अकाली दल परिवारवाद के आरोप झेल रहा है, महाराष्ट्र में शिवसेना की दूसरी-तीसरी पीढ़ी विरासत की राजनीति का सुख भोग रही है। विडंबना यह भी है कि हमारे यहां व्यक्तियों के नाम पर दल बन रहे हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि के उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि राजशाही को समाप्त करने के बाद हमने अपने जनतंत्र को परिवारशाही के हाथों में क्यों सौंप दिया? यह सही है, और राहुल गांधी ने भी अमेरिका में यह बात कही कि भले ही कोई परिवार के कारण राजनीति में आया हो, पर उसे अपनी योग्यता प्रमाणित करनी पड़ती है, चुनाव जीतना पड़ता है।

अब पासवर्ड याद रखने की नहीं होगी जरूरत

तकनीक जाइंट गूगल अब ऐसी तकनीक लेकर आ रहा है जिससे यूजर्स को अपने अकाउंट का पासवर्ड याद रखने या डालने की जरूरत नहीं रहेगी। गूगल का यह नई तकनीक वाला लॉगइन सिस्टम ट्रस्ट पर बेस्ड होगा। इसका मतलब अगर किसी डिवाइस को विश्वास होगा कि आप ही इसे यूज कर रहे हैं, तभी वह आपको अपना ऐक्सेस देगा।

इस नाम से चल रहा प्रोजेक्ट पर काम

खबर है कि गूगल के इस प्रॉजेक्ट का नाम अबेकस है और यह ट्रस्ट एपीआई पर आधारित है। इसे गूगल ने डेवलपर आई/ओ कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश किया था। इस तकनीक की टेस्टिंग गूगल जून से शुरू कर रहा है। फिलहाल इस सिस्टम को स्मार्टफोन्स के लिए तैयार किया गया है। यह सिस्टम यह देखेगा कि आप किस तरह से अपने हैंडसेट को यूज कर रहे हैं। यह इसके लिए पर्सनल इंडिकेटर्स पर नजर रखकर असली यूजर्स को पहचानेगा।

WEB कॉर्नर

ऐसा पासवर्ड करेगा एक्सेप्ट

इस तकनीक में पासवर्ड डालने के लिए कहने की बजाय आवाज, चेहरे, टाइप करने के तरीके, चाल–ढाल वगैरह के आधार पर पहचान होगी। इन सब बातों को एक डेटा के रूप में कंपाइल करके यह उसे एपीआई में डालकर ट्रस्ट स्कोर बनाएगी। इसके बाद ही वह तय करेगा कि फोन को यूज कर रहा यूजर कौन है।

सुरक्षित तकनीक

इस तकनीक को इसलिए सुरक्षित माना जा रहा है क्योंकि पासवर्ड को चुराया जा सकता है, लेकिन आवाज, चाल–ढाल, चेहरे वगैरह से मेल करवाना आसान काम नहीं है। इस वजह से सिक्योरिटी और अधिक बढ़ जाती है। गूगल का मानना है कि यह सिस्टम फिंगरप्रिंट स्कैनिंग से 10 गुना ज्यादा सेफ है। गूगल का कहना है कि यदि सब कुछ सही रहा तो इस साल के अंत तक यह तकनीक गूगल डेवलपर्स के पास होगी। इसका मतलब यूजर्स को जल्द ही पासवर्ड याद रखने के झंझट से छुटकारा मिलने वाला है।

■ पाठकों के पत्र

महिलाओं की उपेक्षा कब तक

सिर्फ एक दिन के लिए महिलाओं का गुनगान करके उन्हें सम्मान देना और दूसरी और उनको छलना, उनके साथ कपट भाव रखना, रास्ते चलते छेड़छाड़ करना, स्त्री को लज्जित करना, शराब पीकर महिलाओं के साथ मारपीट करना ...यह सब पुरुष वर्ग को शोभा नहीं देता। इससे अच्छा यही होगा कि हम महिला दिवस मनाना ही भूल जाएं। अगर सच में महिलाओं के प्रति हमारे मन में आदर और सम्मान है तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम उन मां, बहन, बेटियों, बहुओं और उन मासूम बच्चियों के प्रति पहले ते अपना नजरिया बदलें और उन्हें हीन दृष्टि से देखना बंद करें। पराए घर की किसी महिला या लड़की को हम हमारी घर की बेटी समझ कर उन्हें भी उसी नजरिए देखें, जो नजरिया हम अपनी मां और बहनों के लिए रखते करते हैं। महिला दिवस मनाने का केवल यह मतलब नहीं है कि एक दिन तो बहुत ऊंचे स्थान पर बैठाकर मान-सम्मान दे दिया जाए और दूसरे ही दिन राह चलती लड़कियों से छेड़खानी शुरू कर दी जाए। यहां युवा तो युवा, बुजुर्ग भी इन मामलों में पीछे नहीं है। रास्ते चलते महिलाओं-लड़कियों पर फब्ति?यां कसना इनकी आदत शुमार में है और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो तब हो जाती है जब हैवानों का दल 3-5 साल की मासूम बच्चियों को भी अपना निशाना बनाने में नहीं चूकते और मौका देखते ही उनका शीलहरण करके उन्हें नारकीय जीवन में पहुंचा देते है। कभी टॉफी का लालच देकर तो कभी अन्य बहानों से बहला-फुसलाकर अपने नापाक इरादों को उन मासूमों पर थोप दिया जाता है।

-रितुराज वर्मा, मुंगेली

■ जरा इनकी भी सुनिए

शशिकला के पास अस्पताल में भर्ती जयललिता का एक वीडियो है। इसमें जयललिता ने गाउन पहना था। उन्होंने वीडियो को पब्लिक करने से मना कर दिया। यही नहीं उन्होंने कहा कि इस वीडियो को वे जांच समिति को देंगे।

-टीटीवी दिनाकरण
एआईएडीएमके नेता

पीएम पूरे विश्व में आतंकवाद के मुद्दे को प्राथमिकता देने में सफल हुए। मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश बखूबी किया है। पाकिस्तान से हम दोस्ती चाहते हैं इसलिए पीएम प्रोटोकॉल छोड़ पीएम शरीफ से मिलने गए थे।

-नितिन गडकरी
केंद्रीय मंत्री

ट्विट ट्विट

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जो कोई भी इसमें पकड़ा जाएगा वो बचेगा नहीं।

-नरेंद्र मोदी

करीब चार दशक का अनुभव रखने वाले सेना के तीनों अंगों के प्रमुख का इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। इसमें कहा गया है कि रक्षा सचिव देश की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।

-पीवी नाइक